Indian Dairy Corporation and National Dairy Development Board is under consideration.

(b) No, Sir.

(c) At present there are two nominees of the Government of India on the Boards of Directors of Indian Dairy Corporation/National Dairy Development Board.

देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी०ए० के "दांत" शीर्षक से छपा समाचार

3317. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर 1986 के जनसत्ता में "देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी० ए० के दांत" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले की कोई जांच करायी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामवासियों को नोटिस जारी किए गए थे और यदि हां, तो ऐसे नोटिस कितनी बार तथा किस-किस तारीख को दिए गए थे :

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाये हैं यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं : और

(घ) 1984 के संशोधित कानून के अधीन ग्रामवासियों को नोटिस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां । राष्ट्रीय राजधानी के सतत विकास को देखते हुए दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली में भूमि का अर्जन किया जा रहा है ।

(ख) भूमि के अधिग्रहण के नोटिस दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि पिछले कई वर्षों से चरणों में अधिग्रहित की गई है और भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिसूचनाएं व नोटिस समय-समय पर संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं ।

(ग) दिल्ली के सुनियोजित विकास के अंतर्गत भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ।

(घ) निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण के लिए संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 तथा 10 के अंतर्गत नये नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अनुसूजित जातियों/अनुसूजित जनजातियों के लिए सलाहकार बोर्डों का स्थापित किया जाना

3318. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा क ग कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान में ऐसे क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए एक सलाहकार परिषद के नियुक्त लिए जाने का उपबन्ध है, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती हो और जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती हैं, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सलाहकार बोड का गठन किया गया है, और

(ग) क्या बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में इस प्रकार के सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है; यदि हां, तो क्या बोड कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमागों) : क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में, प्रत्येक राज्य में